FOLLOW US ON: Anokha Teer Harda @anokhateer

दैनिक अनोखा तीर की पाक्षिक प्रस्तुति...

तपती धरती

हरदा- शुक्रवार 01 सितम्बर 2023

www. anokhateer.com

दुनिया के तमाम देश धरती पर बढ़ते तापमान को लेकर चिंतित है। जिसके चलते जलवायु परिवर्तन का असर और उसके दुष्परिणाम पृथ्वी पर देखने को मिलने लगे है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लेकर चीन, रोम, फिनिक्स जैसे कई देशों में अगस्त माह में भी गर्मी 50 सालों का रिकार्ड तोड़ रही है। ऐसी स्थिति में तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि धरती पर बढ़ते इस तापमान को पेड़ लगाकर जल निकायों को बहाल करते हुए प्राकृतिक संसाधनों से ही इस ताप लहर से धरती और उस पर रहने वाले जीवन को बचाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी आव्हान किया है कि अपने व्यापार को पर्यावरण अनुकूल बनाया जाए। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए दुनिया के विशेषज्ञ कागजी कार्ययोजनाएं बनाकर उसके निदान की वकालात कर रहे है तो वहीं भारत के हृदय प्रांत मध्यप्रदेश में लोकल वार्मिंग के निदान की दिशा में जमीनी स्तर पर ठोस कार्य किए जा रहे है।

नर्मदांचल ने रचा पौधरोपण का इतिहास

पौधरोपण की जमीनी हकीकत से रूबरू हो रही देश विदेश की कंपनियां

मध्यप्रदेश के नर्मदांचल में पिछले लम्बे समय से हरदा के पर्यावरणविद् गौरीशंकर मुकाती की अगुवाई में जहां वृक्षारोपण के माध्यम से नदी-नालों को सदा नीरा बनाने की दिशा में पहल की जा रही थी। वहीं अब श्री मुकाती ने रूपई एग्री फॉरेस्ट प्रायवेट लिमिटेड के बैनर तले अपनी इस मुहिम को प्रदेश और देश की सीमाओं से बाहर निकालकर विदेशों तक पहुंचाने का कार्य किया है।

1 करोड़ 20 लाख पौधे रोपण

बीते वर्ष जहां अलग-अलग कार्ययोजनाओं के तहत 20 लाख पौधों का रोपण किया गया था तो वहीं इस वर्ष नर्मदा के तटवर्तीय क्षेत्रों में 1 करोड़ 20 लाख पौधरोपण का महाअभियान चलाकर इतिहास रच दिया है। बीते दिनों जहां साउथ कोरिया की टीम ने इस वृक्षारोपण अभियान का मौका मुआयना करते हुए इसकी प्रक्रिया को नजदीक से समझा था तो वहीं गत दिवस विभिन्न कंपनियों ने इस अभियान की जमीनी हकीकत से रुबरु होते हुए अपनी भावी कार्ययोजनाओं की रुपरेखा तैयार की। एचडीएफसी बैंक द्वारा बीते वर्ष श्री मुकाती के नेतृत्व में ही 5 लाख पौधों का प्रोजेक्ट चालू किया गया था। इस कार्ययोजना के सफल क्रियान्वयन का भौतिक सत्यापन करते हुए हाल ही में एचडीएफसी की एक टीम ने अपने भविष्य की कार्ययोजना पर भी चर्चा की। इसी तरह 1 करोड़ 20 लाख पौधरोपण का महाअभियान वाली व्हीएनव्ही की टीम के अमित चौहान, प्रवीण गोयल आदि ने भी जमीनी स्तर पर इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन को देखा। वहीं इम्पका सर्विस प्रायवेट लिमिटेड मुम्बई के डायरेक्टर विक्रांत तिवारी, सुप्रिया पाटिल, इकबाल नैय्यर, प्रवीत श्रीवास्तव आदि ने इस कार्ययोजना को देखा और समझा है। वहीं बीते वर्ष 6 लाख पौधों का रोपण करा चुकी मुम्बई के ग्रो-ट्रीज कंपनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विपुल, रौनक जरीवाला, अमंदा आदि ने भी इस पौधरोपण मॉडल का अवलोकन किया।

आसान नहीं है निजी भूमि पर करोड़ों पेड़ लगाना

शासन का भारी भरकम वन अमला लाखों हेक्टेयर वन भूमि पर करोड़ों रुपए खर्च कर भी जो कार्य नहीं कर पाता है वह निजी तौर पर करना कितना दुश्कर होता है। लेकिन इस कार्य को रुपई एग्री फॉरेस्ट के एमडी गौरीशंकर मुकाती और उनकी टीम ने कर दिखाया है। 1 करोड़ 20 लाख पौधों को 27 हजार किसानों के लगभग 50 हजार से अधिक खेतों की मेड़ों पर हजारों मजदूरों को रोजगार देते हुए रोपण किया गया। योजना के क्रियान्वयन क्षेत्र में लगभग 10-10 एकड़ की 6 नर्सरियों में डेढ़ करोड़ से अधिक रोपे तैयार किए गए। जिसके आधार पर खेतों की मेड़ों पर लगभग 85 लाख सागौन, 3 लाख खमेर, 60 हजार शीशम, लगभग 10 लाख फलदार पौधे और 8 लाख बांस का रोपण किया जा चुका है। वहीं लगभग 19 लाख फलदार पौधों का रोपण किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। मात्र एक सीजन में इतनी बड़ी तादाद में इस पौधरोपण कार्य को किस तरह चैन बनाकर सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाता है इसी प्रक्रिया को देखने विभिन्न कंपनियां यहां पहुंच रही है। जिसके आधार पर वह अपनी भावी योजनाएं भी तैयार कर रही है। निश्चित ही यह पौधरोपण महाअभियान मध्यप्रदेश ही नहीं बल्कि देश में एक अनूठा है जिसे विदेशी कंपनियां भी पसंद करते हुए अपने प्रोजेक्ट यहां लागू करने के लिए ललायित नजर आती है।

जंगल की आग की घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना जरूरी

> “आजकल जंगलों की आग की खबर प्रतिदिन सुनाई देती है। वर्तमान में ग्रीस धधक रहा है इसके पूर्व केलिफोर्निया, कनाडा, आस्ट्रेलिया एवं फ्रांस के जंगलों की आग की खबरें प्रमुखता से छाई रही। भारत भी जंगलों की आग से अछूता नहीं है अकेले उत्तराखंड में वर्ष 2021 के पहले छह माह में आग लगने की 1000 घटनायें सामने आयी। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश एवं गुजरात में जंगल की आग की घटनाओं के मामलों में एफएसआई ने उच्च प्रवर श्रेणी में रखा है।”

मनोज पांडे
सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी, भोपाल

जंगलों की आग का पर्यावरण, जैव विविधता, आर्थिक एवं समाज के हर पहलु पर दुष्प्रभाव पड़ता है जैसे जैव विविधता को हानि, जंगल के आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण में वृद्धि, भूमि उर्वरता में कमी, जंगल की आग से वन संपदा को भारी नुकसान के साथ साथ अनेक प्रजातियों की दुर्लभ वनस्पति, जीव जंतु, जड़ी बूटियाँ नष्ट हो जाती है या विलुप्त होने की आशंका बनी रहती है। वनोंत्पाद पर निर्भर भारत में 1.70 लाख गांव की जनता जंगल की आग आजीविका विहीन हो जाते हैं। आग से जंगल पर आधारित उद्योगों, रोजगार एवं पर्यटन को हानि होती है। जंगल में आग लगने से बहुत सारे बीज नष्ट हो जाते हैं, जिससे पौधों का प्राकृतिक उत्पादन नहीं होता है, भूमि का कटाव शुरु हो जाता है, भूमि के पोषक तत्व, पीएच तथा पानी को रोके रखने की क्षमता प्रभावित होती है। वैश्विक स्तर पर 1.76 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन के लिए जंगल की आग जिम्मेदार है, जो कुल उत्सर्जन 36 बिलियन टन का 5 प्रतिशत है।

जंगल में आग लगने के मानवीय और प्राकृतिक दो महत्वपूर्ण कारण है। मानवीय कारणों में मजदूरों द्वारा साल के बीज, शहद, महुआ इत्यादि एकत्रित करने के लिए जंगल में आग लगाई जाती है, अन्य कारणों में आसपास के गांव के लोगों द्वारा दुर्भावना से, जंगल में लगने वाले केम्प में भोजन बनाने के बाद आग ठीक से न बुझाना, जलती हुई बीड़ी सिगरेट फेंकना, बिजली के तारों का वन से गुजरना, हरी घास उपलब्ध कराने के लिए आग लगाना। रेल इंजन, बस के धुयें से निकलने वाली चिंगारी भी कई बार आग का कारण बन जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में झूम की खेती भी जंगल की आग प्रमुख कारण है। झूम की खेती में एक विशेष क्षेत्र में आग लगा कर दो तीन वर्षों तक खेती की जाती हैं एवं जब जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो उस क्षेत्र को छोड़कर नये क्षेत्र को खेती हेतु चुना जाता है। छोड़े गये क्षेत्र में कुछ वर्षों में फिर से वन हो जाता है।

आग लगने के प्राकृतिक कारणों में आकाशीय बिजली गिरना, गिरती हुई चट्टानों की आपसी रगड़, सूखे पेड़ पौधों जैसे बांसों की रगड़ के अलावा पहाड़ों पर चीड़ का मोनोकल्चर प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। पर्वतीय क्षेत्रों में चीड़ के पेड़ बहुतायत में पाये जाते हैं। वर्ष 2005 से 2015 के बीच कमाऊँ के जंगलों में आग लगने की 2238 घटनाओं में 5356.77 हेक्टेयर क्षेत्र के जंगल आग की भेंट चढ़ गए। किसी वार्षिक त्योहार की भांति यह क्रम आज भी जारी है। चीड़ के वृक्ष की पत्तियाँ जिन्हें स्थानीय भाषा में पिरुल कहा जाता है आग फैलने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा चीड़ के पेड़ से निकलने वाला मूल्यवान पदार्थ लीसा है। लीसा एक तरल द्रव्य है जिसमें आग लगने के पर पेट्रोल की भांति आग फैलती है तीसरा चीड़ एक ऐसा पेड़ है जो शुष्क भूमि पर उगता है एवं पानी के स्त्रोतों को खत्म करता है एवं मिट्टी की पकड़ कमजोर करता है

जंगल की आग तीन प्रकार की होती है। प्रथम धाराग्नि अथवा ग्राउंड फायर, यह उन वनों में लगती है जहां सूखे पत्ते, कूड़ा करकट अधिक मात्रा में होता है। इस आग में लपटें नहीं निकलती है तथा धुआँ भी कम निकलता है परन्तु अधिक हानिकारक होती है। तथा यह आग फैलती है एवं लंबे समय तक लगी रहती है। द्वितीय तलाग्नि अथवा सरफेस फायर, यह आग सूखे पत्तों, घास एवं पेड़ के निचले भाग में लगती है, इसमें लपटें निकलती है एवं कम हानिकारक होती है। तीसरी छत्राग्नि अथवा क्राउन फायर, यह आग पेड़ की ऊंचाई पर लगती है तथा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फैलती है। यह आग प्रायः शंकुधारी वनों में लगती है। दक्षिण अमेरिका के वनों में इपीलोबियम अनगस्टीफोलियम नामक एक अग्नि सूचक वनस्पति पायी जाती है। सामान्यतः यह छोटे-छोटे पेंचों में रहती है परन्तु जब जंगल में आग लगती है तो यह तेजी से क्रियाशील होकर पौधा बन जाती है।

जंगलों में लगी आग कम करने अथवा बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है जंगलों में कंट्रोल अथवा नियंत्रित फायर करना। वन विभाग द्वारा एक निश्चित क्षेत्र के जंगल में आग लगा कर जला देना। इसे कंट्रोल फायर लाइन कहा जाता है। इससे होता यह कि आग कहीं भी लगे कंट्रोल फायर लाइन तक आकर थम जाती है। वर्तमान में केवल उत्तराखंड में 9000 किमी कंट्रोल फायर लाइन की जरूरत है परन्तु 2500 किमी मौजूद है अर्थात कंट्रोल फायर लाइन का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। कंट्रोल फायर के कुछ अन्य लाभ यह है कि घास, खरपतवार एवं अवांछनीय प्रजाति के पौधे नष्ट हो जाने से बीजों के अंकुर के लिए भूमि खाली हो जाती है एवं पौधों में वृद्धि हेतु प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है।

आग लगने पर बुझाने हेतु सर्वप्रथम सूचना वन विभाग को देना चाहिए जिससे फायर फाइटिंग स्टाफ अपने यंत्रों के साथ प्रभावित स्थल तक पहुंच सके। आग लगने की जगह पर उपलब्ध मिट्टी से एवं नीचे लगी आग को टहनियों या पीटने वाले यंत्र द्वारा बुझाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आग लगने की दिशा के विपरीत दिशा में जानबूझ कर प्रत्याग्नि लगाई जाती है जब बढ़ते बढ़ते दोनों आग मिल जाती तो आग स्वयं बुझ जाती है।

भारतीय वन दुनिया के अत्याधिक विविधता वाले वनों में से एक है। अधिकारिक तौर पर भारत में लगभग 802088 वर्ग किमी में वन है। यह कुल क्षेत्रफल का 21.67 प्रतिशत है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के लक्ष्य के अनुसार भारत के वन क्षेत्र में एक तिहाई विस्तार करना है। भारत में वनों का संरक्षण भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के कार्यान्वयन और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के माध्यम से किया जाता है। इसके तहत भारत सरकार ने 597 संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की है, जिनमें 597 राष्ट्रीय उद्यान एवं 500 वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन नीति 1988 में वनों में लगने वाली आग पर नियंत्रण के लिए विशेष सावधानी बरतने की बात कही गई है लेकिन इस बात का आपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल पायी है। वहीं दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या, वन आधारित उद्योगों एवं कृषि भूमि के विस्तार के कारण वन भूमि पर भारी दबाव है एवं संशाधन के प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

वास्तविक स्थिति एवं जंगल की आग घटनाओं पर नियत्रंण हेतु कौन-कौन से कदम उठाने की जरूरत है इस विषय पर प्रकाश डालना आवश्यक है। भारतीय कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञों के दल ने अपनी रिपोर्ट में देश में जंगल की आग को बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि आर्थिक एवं पारिस्थितिकी दृष्टि से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। वन कर्मचारियों के प्रशिक्षण और आग से बचाव की तकनीक पर भी ध्यान नहीं दिया गया। आग पर नियंत्रण की कोई स्पष्ट योजना नहीं है। वन से जुड़ी अर्थव्यवस्था पर आग के प्रभाव के प्रति जागरूकता का बहुत सीमित है। जंगल की आग संबधी आंकड़े अविश्वसनीय, अव्यवस्थित एवं नाममात्र के है। भारत को एक संपूर्ण वनाग्नि प्रबंधन की आवश्यकता है इसके लिये केंद्र सरकार को प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं जागरूकता संबधी सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। राज्य के पास जंगल की आग से निपटने के पर्याप्त साधन नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में आग के फैलाव रोकने एवं एक क्षेत्र तक सीमित रखने की समुचित व्यवस्था नहीं है। वन क्षेत्र के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन एवं आग पर नियत्रंण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके मद्देनजर जंगल की आग प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाना जरूरी है। वर्तमान में 21 राज्यों ने अपनी वनाग्नि प्रबंधन योजना केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्तुत की है जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड द्वारा प्रस्तुत योजना को केन्द्र की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। 1992 में रियो में हुये पृथ्वी सम्मेलन के 21वें मसौदे के पैरा 11.2 में जंगल में फैलने वाली आग से उत्पन्न होने वाली समस्यायों पर विस्तार से चर्चा की गई थी।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि जंगल की आग में तीव्रता में वृद्धि का कारण प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों है, तथा यह भी सत्य है कि जंगल की आग आज बड़ी आपदा का रूप ले चुकी है। भारत एवं विश्व में वनाग्नि बढ़ने से सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण असंतुलन आ जाता है। इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए वनों में समुदाय की भागीदारी को और अधिक बढ़ा कर इस समस्या के समाधान के लिए सार्थक कदम उठाने चाहिए।

अलनीनो और भारतीय मानसून

जलवायु परिवर्तन इस समय की सबसे बड़ी त्रासदी है। पूरा विश्व असामान्य वर्षा, असामान्य तापमान, बाढ, तूफान, जंगलों में आग, सूखा आदि विभीषिकाओं से जुझ रहा है। अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में तापमान 7 प्रतिशत तक बढ़ गया है। लगभग सभी देशों के वनों का एक बड़ा हिस्सा आग लगने से स्वाह हो चुका है। अभी ग्रीस और अलजेरिया के वनों में आग लगने की खबरें हैं।

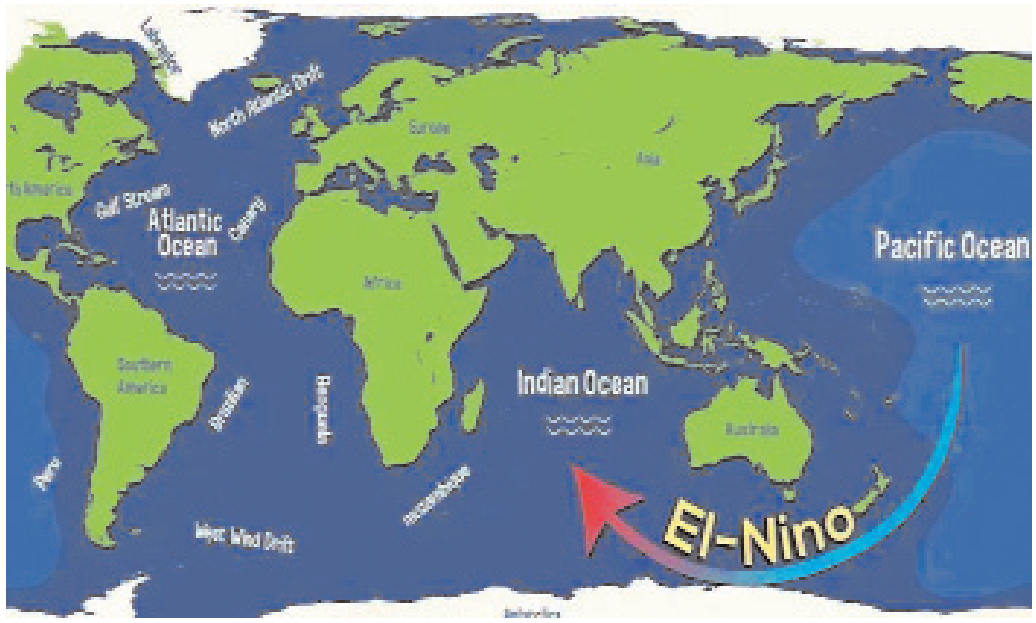

हिमालयीन प्रदेशों में बादल फटने की घटनाएँ लगातार सुर्खियों में हैं, जिससे नदियों में बाढ़ आने से बाँध, पहाड़ सड़कें टूट रही हैं। उत्तराखंड में सोनाली नदी का बाँध टूटकर बह गया। इसी बीच मौसम वैज्ञानिकों ने अलनीनो से अधिक तबाही होने की आशंका जताई है जो इस वर्ष के अंत में आ जाएगा। जिससे पूरे विश्व में तापमान 1.5 से 3 डिग्री तक बढ़ने से भयानक गर्मी की चपेट में आ जाएगा। जिससे वनों में आग लगने की, जलाशयों के सूखने की तथा वर्षा की मात्रा कम होने जैसी आपदाएं तीव्र गति से बढ़ जाएगी। ग्लेशियर तेज गति से पिघल जाएंगे। फसलों का उत्पादन कम हो जाएगा। हाल का एक जलवायु अध्ययन बताता है कि विश्व के 65 प्रतिशत जलाशय सूखने की कगार पर हैं, जिसका कारण धरा पर बढ़ता तापमान है।

■ श्रीमती मनोरमा पंत
भोपाल
(लेखिका वरिष्ठ साहित्यकार है)
मोबाईल -9229113195

इतने भयावह दुष्परिणाम वाला अलनीनों है क्या?

आइये अब अलनीनो के बारे में बात करें। उष्ण कटिबन्ध में स्थित प्रशांत महासागर का वह भाग जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आता है, के महासागर के तापमान और वहां के वायुमण्डलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिये जो समुद्री घटना उत्तरदायी है उसे ही अलनीनो कहा जाता है। यह घटना दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वोडर, चिली और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में तीन से सात वर्षों के अंतराल पर होती रहती है जिससे वहां के समुद्री तापमान में बढ़ोत्तरी होती जाती है।

इस घटना को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। पूर्व प्रशांत महासागर के ऊपर की हवाओं तथा उसके समुद्री सतह के तापमान में एक अवधि में अनियमित बदलाव होता रहता है। यह बदलाव ही अलनीनो कहलाता है। यह अवधि तीन वर्ष से सात वर्ष की हो सकती है। अलनीनों का आविर्भाव क्रिसमस के समय के आसपास होता है।

इस अवधि में प्रचलित हवाओं की दिशा बदल जाती है, वे कमजोर पड़ जाती है और समुद्री सतह का तापमान बढ जाता है। इस दौरान प्रचलित वर्षा क्षेत्र का चरित्र बदल जाता है। अधिक वर्षा क्षेत्रों में कम वर्षा होती है और कम वर्षा क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। जब दक्षिण अमेरिका में भारी वर्षा होती है तो आस्ट्रेलिया एवं इन्डोनेशिया में सूखा पड़ जाता है।

विपरीत दशाओं में अलनीनों के कारण पूर्वी हवाओं के कमजोर पड़ने से दक्षिण अमेरिका में कम वर्षा होती है। इस अवधि में पेरु की ठंडी जलधारा को विस्थापित कर गर्म जलधारा विकसित होने लगती है, जिससे समुद्री सतह का तापमान बढ़ने लगता है और गर्म जल का प्रवाह हिन्द महासागर की ओर होकर वहां के सतही तापमान में वृद्धि कर देता है, जिससे वहां स्थित वायुदाब की तीव्रता कम हो जाती है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून पवने कमजोर हो जाती हैं।

अलनीनों के जन्म के लिये 'दक्षिणी दोलन' को उत्तरदायी माना जाता है, इसे अंग्रेजी में southern osillation कहा जाता है। दोलन का अर्थ है झूलना। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी प्रशान्त महा सागरों तथा पूर्वी हिंद महासागर दोनों के बीच वायुदाब कभी अधिक कभी कम होने के बीच झूलता रहता है। यह घटना 3 डिग्री से 18 डिग्री दक्षिण के बीच होने से इसे दक्षिणी दोलन कहा जाता है। दक्षिणी दोलन के उष्ण कटिबंधीय चरण को एल नीनो तथा तथा शीत चरण को ला नीना कहा जाता है।

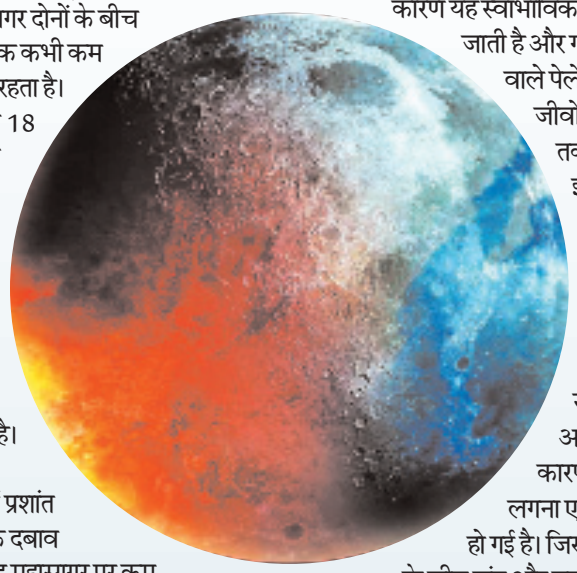

आमतौर पर उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर पर अधिक दबाव रहता है और पूर्वी हिंद महासागर पर कम दबाव रहता है। प्रचलित स्थिति में ग्रीष्मकाल में भारतीय महासागर पर अधिक वायुदाब रहता है। यह स्थिति भारतीय मानसूनी वर्षा के लिए अनुकूल होती है। जब भारतीय महासागरों से चलने वाली वर्षा वाहिनी पवनों से पूरे देश में वर्षा होती है। पर अलनीनो के कारण वहां वायुदाब की तीव्रता कम होने से दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाता है और वर्षा कम होती है। इस अवधि में समुद्री सतह का तापमान सात डिग्री तक बढ सकता है, जिससे भयानक गर्मी पड़ती है।

अभी तक वर्ष 2016 को अलनीनो प्रभाव के कारण इतिहास का सबसे गर्म वर्ष के रुप में दर्ज किया गया है। हाल में ही निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट ने कहा कि अलनीनों की स्थिति अगस्त से ही मजबूत होती दिख रही है। जुलाई में फ्लोरिडा में समुद्री तापमान 37 डिग्री तक पहुँच गया जबकि सामान्य स्थिति में यह 20 से 25 डिग्री के बीच रहता है। अमेरिका यूरोप के कई हिस्से अभी से धधक रहे हैं। अलनीनों के पूरे मजबूत होने से क्या स्थिति होगी, यह सोच कर दिल दहल जाता है।

दुनिया भर में दिखाई देगा अलनीनों का दुष्प्रभाव

सामान्यतः समुद्रों में गर्म पानी नीचे जाता है और नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है। अलनीनो के कारण यह स्वाभाविक प्रक्रिया बंद हो जाती है और गहरे समुद्र से आने वाले पेलेक्टन (समुद्री जीवों का भोजन) ऊपर तक नहीं पहुंच पाते इस कारण समुद्री जीव जंतु मरने लगते हैं। अधिक गर्म पानी से प्रवाल भित्तियां नष्ट हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। अत्यधिक गर्मी के कारण वनों में आग लगना एक सामान्य सी बात हो गई है। जिसके कारण जंगलों के जीव जंतु और वनस्पतियां समाप्त हो जाते हैं। जंगलों के जलने से निकलने वाला धुआं निकटस्थ बस्तियों के लिए जानलेवा बन जाता है और दमा जैसी बीमारियां फैलने लगती है। अलनीनों के कारण वर्षा की मात्रा में कमी होने से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है, जल्दी पकने से दाना छोटा रह जाता है तथा उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। गरीब देश और गरीब हो जाते हैं।

अलनीनों के कारण भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था को, जो पूर्णतया मानसून पर निर्भर हैं, गहरा धक्का लगता है। हाल में ही जुलाई को मानव इतिहास का सबसे गर्म महीने के रुप में दर्ज किया गया। अभी तीन महाद्वीप नार्थ अमेरिका यूरोप तथा एशिया गर्म लहर की लपेट में हैं। अलनीनो आगे क्या कहर ढहाएगी, किसी को नहीं मालूम।

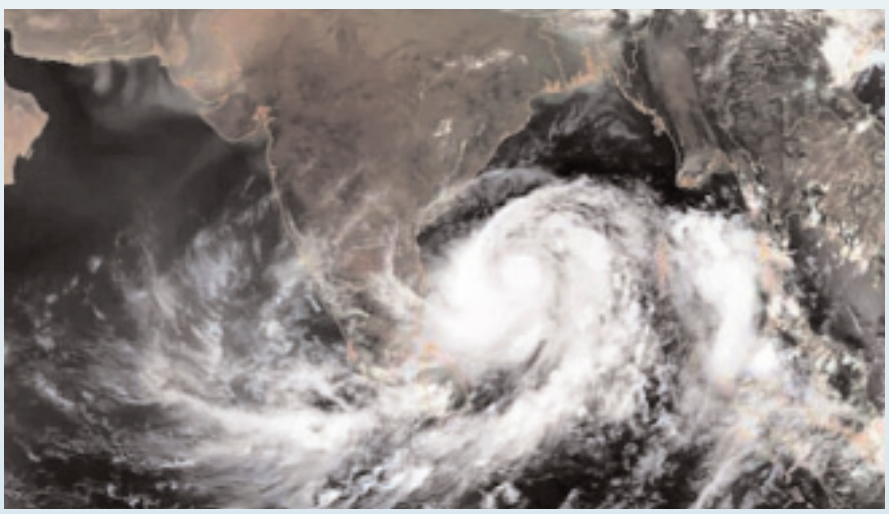

पिछले कई दिनों से सारे टीवी चैनल और अखबार 'बिपरजॉय-बिपरजॉय' चिल्ला रहे हैं। यह अरब सागर में उठा एक अति विनाशकारी चक्रवातीय तूफान है जिसने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों तथा पाकिस्तान में कराची में भीषण तबाही मचाई है। भारत में विनाशकारी तूफान पहले भी आते रहे हैं, फिर 'बिपरजॉय' पर इतना कोलाहल क्यों?

2017 में आयी एक शानदार हिन्दी फिल्म 'कड़वी हवा' में गुलजार साहब की एक अत्यंत मार्मिक कविता है-

'बंजारे लगते हैं मौसम; मौसम बेघर होने लगे हैं।
जंगल, पेड़, पहाड़, समंदर; इंसान सब कुछ काट रहा है,
छील-छील कर खाल ज़मी की; टुकड़ा-टुकड़ा बाँट रहा है,
आसमान से उतरे मौसम; सारे बंजर होने लगे हैं,
मौसम बेघर होने लगे हैं। दरियाओं पर बाँध बने हैं;
फोड़ते हैं सिर चट्टानों से, 'बंदीग लगती है ये ज़मीन;
डरती है अब इंसानों से, बहती हवा पर चलने वाले;
पाँव पत्थर होने लगे हैं, मौसम बेघर होने लगे हैं।'

हम यदि पिछले 25-30 वर्षों में अपने इर्द-गिर्द हो रहे परिवर्तनों और उनके परिणामों पर दृष्टि डालें तो कवि द्वारा रचित शब्दों का यह खेल, क्या अत्यंत कटु यथार्थ सिद्ध नहीं होता है?

पर्यावरण क्या है? मेरी समझ से तो यह हमारा अपना घर है, जिसमें हम सभी रहते हैं। यह कुछ ऐसा नहीं है जो हमसे जुदा हो और हमारे घर के बाहर कहीं दूर स्थित हो और जिसमें होने वाले किसी भी परिवर्तन का हम पर कोई भी प्रभाव न पड़ता हो। कम से कम हमारा भारतीय दर्शन तो यही कहता है। अथर्ववेद के 12 वें अध्याय के प्रथम सूक्त (भूमि सूक्त) की 12 वीं ऋचा इस प्रकार उद्धृत है-

'ध्यं पृथिवि यच्च नभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः संबभूवुः।
तासु नो धेह्यभि नः पवस्व माता, भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः।
पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु ॥12॥'

इसका अर्थ है कि 'हे देवी पृथ्वी, आपके भीतर एक पवित्र ऊर्जा का स्रोत है, हमें उस ऊर्जा से पवित्र करें। हे देवी पृथ्वी, आप मेरी माता हैं और पर्जन्य (वर्षा के देवता अर्थात मेघ) मेरे पिता हैं। आप दोनों ही मिलकर हमारा लालन-पालन करते हैं।' यानि भारतीय दर्शन के अनुसार पर्यावरण से मानव का सम्बन्ध माता-पिता व सन्तान का बताया गया है, अर्थात मानव का अस्तित्व पर्यावरण पर ही निर्भर है। किंतु मानव-बुद्धि की श्रेष्ठता के अहंकार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षमता की सफलता से ओत-प्रोत होकर इंसान ने स्वयं अपने अस्तित्व के लिये संकट खड़ा कर लिया है।

चक्रवात 'बिपरजॉय' के बारे में यदि कुछ दुर्लभ तथ्यों पर हम नजर डालें तो हम इसे समझ पायेंगे। अभी तक अति विनाशक तूफान बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में उठते थे। अरब सागर में इतना विनाशक तूफान पहली दफा ही उठा है। अरब सागर में अब तक यह सबसे लंबे समय तक बने रहने वाला तूफान है। इस दौरान इसकी विनाशक क्षमता (हवाओं की गति) निरंतर बढ़ती रही। 6 जून को मात्र 55 कि.मी. प्रति घण्टे की हवाओं वाला यह तूफान 8 जून तक 130 कि.मी. प्रति घण्टे तथा 10 जून तक करीब 196 कि.मी. प्रति घण्टे वाली हवाओं को धारण कर चुका था। अरब सागरीय क्षेत्र में पानी इतना गर्म पहले कभी नहीं हुआ जितना इस बार।

क्या इन प्रश्नों से हम आँखें चुरा सकते हैं? यह तूफान इतनी विचित्र विशेषताएं क्यों लिये हुए है, क्या हमारे पास इसका उत्तर है?

अब से लाखों वर्ष पूर्व जब हमारे पूर्वज दो पैरों पर खड़ा होना सीख रहे थे और जब उनकी पूँछ हुआ करती थी, तब से लेकर अब तक जब हम लोग मंगल ग्रह तक पहुँच रहे हैं, पर्यावरण ही हमेशा व्यक्ति के अस्तित्व का आधार रहा है। जब मानव इस धरा पर नहीं था, वायु, जल, वन, वन्य-जीव आदि प्राकृतिक तत्व तब भी पृथ्वी पर फल-फूल रहे थे। यानि पर्यावरण से ही हम हैं, हमसे पर्यावरण नहीं है। बिना हवा, पानी, मिट्टी, वनों और जैव-विविधता के हम लोग अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके कारण विश्व की लगभग सभी प्राचीन सभ्यताओं में इन्हें देवतुल्य मानकर इनकी उपासना की गयी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन प्राकृतिक तत्वों में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है वरन इन सभी की स्थिति प्रत्येक गुजरते दिन के साथ बद-से-बदतर होती जा रही है, जिसके लिये स्पष्टतः अनियोजित व अंधाधुंध मानवीय गतिविधियां उत्तरदायी हैं।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि पर्यावरण में होने वाले इस ह्रास का सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ रहा है और हमारे जीवन-स्तर में वास्तविक रूप से गिरावट आती जा रही है। 2013 की केदारनाथ त्रासदी (जिसके चिन्ह आज 10 वर्षों बाद भी साफ देखे जा सकते हैं) 2017 में अमेरिका में आये अति विनाशक चक्रवात 'इरमा' और 'हार्वे' (सिम्पसन स्केल पर क्रमशः कैटेगरी-4 व कैटेगरी-5 के तूफान), 2019 में अटलांटिक महासागर में उठे बेहद शक्तिशाली समुद्री तूफान 'डोरियन' (कैटेगरी-5 क्षमता का तूफान), 2022 में यूरोप की अविश्वसनीय हीट वेव (जिसने 6000 से अधिक जानें ले ली), 2023 में भारत में आया 'बिपरजॉय' चक्रवात तो सिर्फ बानगी हैं। वास्तविकता इनसे कहीं अधिक भयानक रूप धारण कर रही है। यही कारण है कि मानव-बुद्धि की श्रेष्ठता स्थापित करने और अत्याधिक प्रौद्योगिकी विकास करने के बाद भी हमें प्रत्येक वर्ष पर्यावरण संरक्षण के लिये दुनिया भर के ताम-झाम, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, समझौते करने के लिये मजबूर होना पड़ता है।

वास्तव में पर्यावरण में होम्योस्टेसिस क्रियाविधि (अर्थात किसी प्रकार के पारिस्थितिकी असंतुलन को स्वतः ठीक करने वाली स्वचालित क्रियाविधि) कार्य करती है परंतु यदि मानवीय गतिविधियों के फलस्वरुप उत्पन्न पारिस्थितिकी क्षरण की गति इस होम्योस्टेसिस क्रियाविधि को भी पीछे छोड़ दे, उस दशा में हम स्वयं अपना ही अस्तित्व समाप्त करने की इबारत लिख रहे होते हैं।

वर्तमान युग आर्थिक मुनाफे का युग है। किसी भी व्यक्ति या विषय की प्रासंगिकता सिर्फ तभी सिद्ध होती है जब उससे किसी प्रकार का आर्थिक लाभ परिलक्षित होता हो। दुर्भाग्यवश हम भी शायद पर्यावरण संरक्षण के महत्व को तभी समझ सकते हैं जब उसके आर्थिक लाभों को समझ सकें। वास्तव में पर्यावरण हमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अनेक ऐसी सेवायें प्रदान करता है जिनका यदि मौद्रिक रूपांतरण किया जाये तो वह राशि इतनी अधिक होगी जिसकी भरपाई श्रेष्ठ मानव-बुद्धि व अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाना भी असंभव होगा। इन्हें 'पारिस्थितिकी सेवायें' (Ecosystem Services) कहते हैं। जैसे-

1. कृषि – मानव जीवन का आधार कृषि है। क्या बिना मृदा और बिना जल के कृषि कार्य की कल्पना की जा सकती है? क्या बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के खाद्यान्न फसलें, पशुओं के हरे चारे और फलों से लदे वृक्ष हम देख सकते हैं? यहाँ तक कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में भी जल की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। क्या कोई प्रौद्योगिकी मृदा, जल या प्रकाश संश्लेषण का स्थान ले सकती है?

मृदा में रासायनिक कीटनाशक व उर्वरकों के बेतहाशा प्रयोग से उसमें कैंसर कारक तत्वों की मात्रा खतरनाक ढंग से बढ़ रही है जो सब्जियों व अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मानव शरीर व समस्त खाद्य श्रृंखला में भी शामिल हो रही है। इस बात के पुख्ता प्रमाण दिये जा चुके हैं कि वातावरण में लगातार बढ़ती कार्बन डाई आक्साइड के कारण विश्व स्तर पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। जल की उपस्थिति के कारण ही नदी घाटी क्षेत्रों में महान सभ्यताएं विकसित हुईं। हालिया रिलीज तमिल फिल्म 'पोन्नीयन सेल्वन' में 'पोन्नी' नदी (कावेरी) की महिमा का बखान करते एक गीत की शुरुआत इस प्रकार होती है -

'ओ कावेरिया !! तेरी काया,
अम्बर शीश झुकाए।
धरती के माथे की रेखा दिखे तू;
इठलाती-बलखाती ऐसे चले तू,
वीरों के डेरे हैं तेरे किनारे;
घोड़ों की प्यासों को हैं तेरे धारे,'

लगभग इसी प्रकार स्तुति-गान हम अपनी सभी नदियों के बारे में पढ़ते-सुनते आये हैं। लेकिन वास्तव में हमने अपनी नदियों का क्या हाल बना रखा है? उत्तर प्रदेश में गोमती, सई व केरल में पेरियार, चेलियार, तमिलनाडु में ताम्रपर्नी नदियों में अवैध खनन, औद्योगिक प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि इन्हें 'जैविक आपदा (Biological disasters)' घोषित किया जा चुका है। दिल्ली-मथुरा स्ट्रेच में यमुना नदी और कानपुर-वाराणसी स्ट्रेच में गंगा नदी की हालत किसी से छुपी नहीं है। जलवायु परिवर्तन जैसी परिघटना से इस आपदा की तीव्रता में और बढ़ोत्तरी ही होने वाली है, जहाँ नदियों के विलुप्त होने तक की बातें की जा रही हैं।

2. पशुपालन – बहुत दूर न जाते हुये सिर्फ कुछ उदाहरण से इसे समझते हैं। मधुमक्खियों तथा इसी प्रकार के अन्य परागण कीटों की अनुपस्थिति में शुद्ध शहद का निर्माण किस प्रकार होगा? वर्तमान में पूरे विश्व का डेयरी उद्योग दुधारू पशुओं पर टिका हुआ है। क्या कोई प्रौद्योगिकी इन कीटों या दुधारू पशुओं का स्थान ले सकती है? यदि भविष्य में ऐसा होता भी है तो उस प्रौद्योगिकी की कीमत क्या होगी?

3. पारिस्थितिकी संतुलन – यह पारिस्थितिकी सेवाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। निम्न कुछ बिंदुओं पर ध्यान देकर हम इसे समझ सकते हैं:-

- खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल के स्थिरीकरण के संदर्भ में जैव-विविधता की महती भूमिका।
- भू-जैव-रासायनिक चक्र (Bio Geochemical cycle) को संतुलित बनाये रखने में वनस्पतियों, जीवाणुओं और मृदा की भूमिका।
- वनों द्वारा वाष्प-उत्सर्जन के जरिये किसी क्षेत्र में बारिश लाना तथा आर्द्रता, तापमान का यथोचित स्तर बनाये रखना (माइक्रो-क्लाइमेट प्रबंधन)।
- वनों द्वारा मिट्टी को बाँधे रखकर मृदा अपरदन रोकना, भूस्खलन व बाढ़ जैसी आपदाएं रोकना (मैंग्रोव्स वनों द्वारा तटीय अपरदन, सूनामी व चक्रवात से भी बचाव) और भू-जल स्तंभ रीचार्ज में भी अहम भूमिका निभाना।

लेकिन वनीय विनाश और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ते जाने से ये सारी व्यवस्थाएं छिन्न-भिन्न हो रही हैं। इनका सीधा असर मानव जीवन पर पड़ना तय है। केपटाउन में 2018 में 'जीरो वाटर डे' की चेतावनी जारी की गयी थी। दिल्ली एन.सी.आर. क्षेत्र में भी भूजल स्तर खतरनाक ढंग से नीचे जा रहा है।

4. प्रदूषण नियंत्रण व शुद्धिकरण – वनों, यहाँ तक कि छोटे पौधों द्वारा भी प्रदूषण नियंत्रण व वायु शुद्धिकरण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है जो विश्व के सर्वोत्तम एयर प्यूरीफायर द्वारा किया जाना भी असंभव है। इसी प्रकार आर्द्र भूमियों द्वारा भी जल शोधन का सस्ता व प्रभावी विकल्प कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं दे सकता। पूर्वी कलकत्ता आर्द्र भूमि इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है।

5. वैश्विक जलवायु स्थिरीकरण – हमारे महासागर तथा महासागरीय धाराएं वैश्विक जलवायु हेतु अति महत्वपूर्ण हैं। मॉनसून जैसी अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली परिघटना पूर्णतः इन्हीं पर आश्रित है। ये प्रतिवर्ष ग्रीनहाउस गैसों का 30 प्रतिशत भाग भी अवशोषित करते हैं। परंतु सागरीय जल के निरंतर प्रदूषित होने और लगातार बढ़ते ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के फलस्वरुप सागरीय जल के गुण-धर्म तेजी से बदल रहे हैं जिससे पूरी मानव-जाति के सम्मुख अस्तित्व का संकट आ गया है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी का ऊष्मा बजट भी लगातार बिगड़ रहा है जिससे प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति व तीव्रता भी बढ़ रही है।

पर्यावरण की उपरोक्त भूमिकाओं को देखते हुये ही यूएन ने 2020-2030 की अवधि को 'पारितंत्र पुर्नस्थापना का दशक' के तौर पर पहचाना है और 2022 में विश्व के कुल 10 पारितंत्र पुर्नस्थापना प्रोजेक्ट्स को मान्यता व सहायता देने का निर्णय लिया है। इनसे विश्व में करीब 68 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर उनके खोये हुये प्राकृतिक पारितंत्र को न सिर्फ बहाल किया जायेगा बल्कि कुल 15 मिलियन से अधिक रोजगार सृजित किये जा सकेंगे। ये प्रोजेक्ट्स इस प्रकार हैं -

त्रि देशीय अटलांटिक वन परियोजना समझौता (ब्राजील, पैरागुए, अर्जेंटीना)। अबूधाबी समुद्री क्षेत्र परियोजना। अफ्रीका के 11 देशों की संयुक्त महान हरित दीवार परियोजना। नमामि गंगे परियोजना (भारत)। मध्य अफ्रीका व केंद्रीय एशियाई देशों में संचालित बहु-देशीय पर्वतीय क्षेत्र पुर्नस्थापना कार्यक्रम। प्रशांत क्षेत्र में द्वीपीय क्षेत्र पुर्नस्थापना परियोजना। यूरेशिया घास क्षेत्र में संचालित 'अल्टिन डाला' परियोजना। केंद्रीय अमेरिका शुष्क कॉरिडोर परियोजना (6 देशों का संयुक्त समझौता)। इंडोनेशिया का 'बिल्डिंग विथ नेचर' कार्यक्रम। चीन का शान-शुई कार्यक्रम।

फिल्म 'कड़वी हवा' के एक दृश्य में छोटी बच्ची कुहू रात को सोते समय अपने दादाजी हैदू से बताती है 'बाबा, हमाये क्लास में एक लड़का कह रहो कि साल में दुई मौसम होवे-गर्मी और सर्दी। फिर जब सब जने हँस दिये तो माटसाब डपट के बोले 'बरसात को कहाँ गयो?' लड़का बोला ' माटसाब, बरसात तो साल में बस दो-चार दिन ही पड़त है।'

हैदू (भारी आवाज में) - 'सही कही उसने।'
कुहू - 'हमाई किताब में तो चार मौसम लिखो है।'
हैदू - 'पहले होते थे।'
कुहू - 'तो अब काहे नहीं?'
हैदू चुपचाप सो जाता है। कुहू भी फिर सो जाती है।

हर्ष कुमार त्रिपाठी
हर्ष कुमार त्रिपाठी ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बी. टेक. की उपाधि प्राप्त की है तथा DU के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स से भूगोल विषय में परास्नातक किया है। वर्तमान में वे शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के अधीन Govt. Boys. Sr. Sec. School, New Ashok Nagar में भूगोल विषय के प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं।

डिनर टेबल से क्लाइमेट चेंज का क्या है कनेक्शन?

'हाउ बिहेवियरल चेंज कैन टैकल क्लाइमेट चेंज' विषय पर बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों के व्यवहार पर चर्चा की। उन्होंने वैश्विक नेताओं के साथ को चुनौतियों का सामना करने में मददगार बताया। कैसे व्यवहारिक परिवर्तन जलवायु परिवर्तन से निपट सकता है के विषय पर अपनी राय रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर जलवायु परिवर्तन से नहीं निपटा जा सकता। इसके लिए हर घर के खाने की टेबल से शुरुआत करनी होगी। पीएम ने कहा कि जब कोई विचार चर्चा की मेज से खाने की मेज पर जाता है, तो यह एक जन आंदोलन बन जाता है। हर परिवार और हर शख्स को जागरुक करें कि उनके चुनाव इस ग्रह की मदद कर सकते है।

विश्व बैंक में लाइफ की 'हाउ बिहेवियरल चेंज कैन टैकल क्लाइमेट चेंज' विषय पर आयोजित चर्चा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जागरुक लोगों के रोजमर्रा के कामों से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि 'मिशन लाइफ' जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई का लोकतंत्रीकरण करने की एक पहल है।

वैश्विक नेताओं के साथ आने से फायदा!

पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक नेताओं के एक साथ आने से नए विचारों, अंतर्दृष्टि और समाधानों से आगे बढ़ाने के तरीके मिले। ये ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु के भविष्य में सामने आई बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मददगार रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय लोगों को भी सराहा जिन्होंने जलवायु परिवर्तन में सहायता की। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ किया है। लोगों ने भारत के कई हिस्सों में लिंगानुपात में सुधार के प्रयास भी किए। यह वे लोग थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर समुद्र तट, विपरीत समुद्र तटों या सड़कों पर स्वच्छता अभियानों का नेतृत्व किया, ताकि सार्वजनिक स्थान कूड़े से मुक्त हो।

व्यवहार परिवर्तन पर जोर

कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम ने ऊर्जा और संसाधनों के समझदारी से उपयोग और भारत के उपभोग पैटर्न को विनियमित करने से आने वाले बदलावों का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से 22 बिलियन यूनिट से ज्यादा ऊर्जा की बचत होगी। पीएम ने व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिया और बताया कि विश्व बैंक समूह जलवायु वित्त को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करना चाहता है।

लाइफ की विश्व बैंक में 'हाउ बिहेवियरल चेंज कैन टैकल क्लाइमेट चेंज' विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद एक पैनल चर्चा हुई। इसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुईं। पैनल चर्चा के दौरान सीतारमण ने प्रशासन की ओर से किए गए जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयासों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

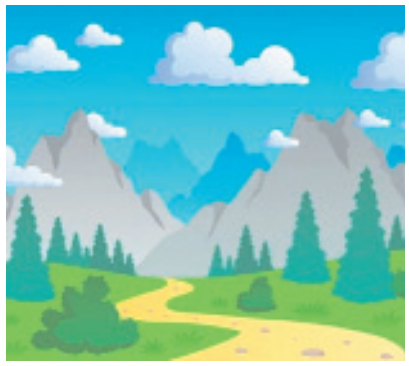

'टूटते बिखरते पहाड़'

टूटते बिखरते पहाड़ हमें,
देते गंभीर संदेश हैं।
प्रकृति से छेड़छाड़ का,
भोगते हम कलेश हैं।।
धूलिया चट्टानों से बना,
हिमगिरि का प्रदेश है।
भुरभुरा है स्वःस्थिर है,
स्वनियंत्रित ये देश है।।
अवैज्ञानिक विकास का,
प्रकृति का उपदेश है।
पहाड़ियों को काट कर,
सरिताओं को बांधकर।
जाल सड़कों का बिछाया,
दुर्ग ऊर्जा के बनाया।।
भूस्खलन ये बादल फटना,
मां प्रकृति का संकेत है।
'टूटते बिखरते' पहाड़ हमें....
हिमगिरि के ये वृक्ष जटायें,
हैं भोले शिव शंकर की।
समा गई थी मातु सुरसरी,
शून्य तीव्रता हो गति की।।
जंगल कटे विकास हुआ,
क्षमता घटी पहाड़ों की।
ग्लोबल वार्मिंग बढ़े धरा पे,
सीमा बढ़े समंदर की।।
प्राकृतिक असंतुलन का,
नित बढ़ रहा परिवेश है।
'टूटते बिखरते पहाड़' हमें,
देते गंभीर संदेश हैं।।

– केशव सिंह

जलवायु परिवर्तन का सेहत पर असर जानने के लिए भारत में बनेगा मुख्यालय

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, हाल ही में भारत और एडीबी के बीच 2023-2027 तक के लिए जलवायु परिवर्तन को लेकर समझौता हुआ है, जिसका मुख्यालय भारत में ही होगा। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट है, जो हर किसी को प्रभावित करता है, लेकिन इसके परिणाम विशेष रूप से गरीब और कमजोर आबादी के लिए विनाशकारी हैं।

पारंपरिक चिकित्सा के बाद अब जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पहल (सीएचआई) का मुख्यालय भारत में बनेगा, जिसकी घोषणा जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के सहयोग से सरकार जी-20 देशों के लिए इसे तैयार करेगी जो सभी देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर नीतियां, अनुसंधान और स्वास्थ्य पहल तैयार करेगा। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित जी-20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारत की इस पहल का सभी देशों ने स्वागत करते हुए लिखित समर्थन दिया है। हालांकि, दक्षिण एशिया से चीन ने इस पर सहमति नहीं दी है, लेकिन अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य को लेकर भारत के नेतृत्व में कार्य करने की सहमति दी है।

छोटे देशों के लिए संजीवनी बनेगा भारत

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, हाल ही में भारत और एडीबी के बीच 2023-2027 तक के लिए जलवायु परिवर्तन को लेकर समझौता हुआ है, जिसका मुख्यालय भारत में ही होगा। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट है, जो हर किसी को प्रभावित करता है, लेकिन इसके परिणाम विशेष रूप से गरीब और कमजोर आबादी के लिए विनाशकारी हैं। वैश्विक दक्षिण क्षेत्र के कम आय वाले देशों के लिए भारत एक संजीवनी बनेगा और जलवायु परिवर्तन से बचाव में सहयोग करेगा।

70 फीसदी संक्रामक बीमारियों की वजह

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव काफी गहरा है। हम देख रहे हैं कि 70 फीसदी संक्रामक बीमारियां जलवायु परिवर्तन की वजह से सक्रिय हुई हैं, जिन्हें जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसमी घटनाएं लोगों के लिए घातक हो रही हैं। वर्षा के परिवर्तनशील पैटर्न से पानी की कमी हो सकती है। ऐसे में सरकार भारत के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर जनमानस के सहयोग के लिए यह पहल शुरू कर रही है।

जलवायु परिवर्तन का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में होना चाहिए

लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हैं। वहीं जलवायु परिवर्तन का मुद्दा देश के विकास की राह में एक सवाल बन कर खड़ा हुआ है। क्या पार्टियां अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल करेंगी। जी-20 की अध्यक्षता में भारत ने जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठाया था। इसके बावजूद जी-20 एजेंडे में जलवायु परिवर्तन और इससे निपटने के लिए अभी तक कोई खास आकर्षण नहीं देखा गया। लेकिन वैज्ञानिकों की चेतावनी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव की तरफ से जिस तरह से जी-20 देशों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को रोकने की बात कही गई है। उस पर ध्यान देने की जरूरत है।

बता दें कि 1 दिसंबर 2022 से भारत दुनिया के महत्वपूर्ण संगठन जी-20 नेतृत्व कर रहा है। जी-20 देशों के समूह की अध्यक्षता संभालते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत दुनिया में एकता की सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा।

भारत 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के मंत्र के साथ आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने जोर देकर ये भी कहा था 'जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी की चुनौतियों को एक-दूसरे से लड़कर नहीं, बल्कि केवल एक साथ काम करके हल किया जा सकता है।'

बता दें कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। भारत ने व्यापार में देश की बढ़ती क्षेत्रीय भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इसके कुछ खतरनाक परिणाम भी सामने आए हैं। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बढ़ोत्तरी भी इसी का एक उदाहरण है। भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी बनाए हैं। भारत 2027 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर अब तक जोर देता रहा है। इसी सिलसिले में देश ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) की बैठक में 27 वें सम्मेलन में अपनी रणनीति भी साझा की है। भारत लंबे समय के लिए ग्रीन हाउस के कम उत्सर्जन की रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत ने इस मुद्दे पर नीतिगत प्रतिक्रियाओं को तैयार करने में अहम भूमिका भी निभाई है। इससे भी जरूरी बात यह है कि वर्तमान संसद विशेष रूप से 2019 के भारतीय आम चुनाव में चुनी गई 17 वीं लोकसभा ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के लिए कानूनों और विधायी उपायों पर बहस भी की। संसद में की गई बहस में वायु और जल प्रदूषण से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा भी हुई थी। सांसदों ने यूएनएफसीसीसी, पेरिस समझौते और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के तहत भारत में हो रहे जलवायु परिवर्तन पर जवाब मांगा।

लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही उर्जा को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने, वायु प्रदूषण से निपटने, फसलों के अपशिष्ट से होने वाले प्रदूषण को काबू करने की दिशा में कई सवाल सामने आ खड़े हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन से देश के अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों को कई तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जो भारत की रणनीति पर सवाल खड़े करने लगा है।

हीटवेब ने भी बढ़ाई चिंता

बढ़ती हीटवेब की वजह से 2023 में 13 से 20 फरवरी के बीच लगभग 1,156 जंगल आग की चपेट में आए। जलवायु संबंधी आपदाओं की वजह से भारत में 4.9 मिलियन लोगों के आंतरिक विस्थापन की भी सूचना मिली है। देश में राजनीतिक नेतृत्व को न केवल अपने घोषणापत्रों और कार्यों में सामान्य उपायों को मजबूत करने की जरूरत है, बल्कि लोगों के सामने आ रही दुशवारियों को भी को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और लचीलेपन पर भी निर्माण लेने की जरूरत है।

सत्तारूढ़ बीजेपी के 2019 के घोषणापत्र में पर्यावरण संरक्षण का भी जिक्र था। ये नवीकरणीय ऊर्जा, वनीकरण और वन्यजीव आवासों के संरक्षण के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर केंद्रित था। बीजेपी ने ऐसी नीतियां लाने का भी संकल्प लिया था जो विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत टिकाऊ नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरी तरफ कांग्रेस जलवायु परिवर्तन से निपटने के सरकार के तरीके की मुखर आलोचना करती रही है। बता दें कि कांग्रेस ने 2019 के घोषणापत्र में पार्टी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय जलवायु आयोग बनाने और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लाने का वादा किया था।

अब देखना ये होगा कि इस बार के घोषणापत्र में तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर अपने रुख को कितना सही साबित कर पाती है। क्या पार्टियां जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई नीतियों को पेश करेंगी। हाल के कई रिपोर्टों में भारत जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कमजोर देशों में से एक देश बन कर उभरा है। ऐसे में यह तय करना जरूरी लगता है कि 2024 के चुनावों से पहले देश की राजनीति में जलवायु परिवर्तन को रास्ते पर लाने के वादे कहां अपनी जगह पाते हैं।

युवा मतदाताओं का फोकस

यह मुद्दा युवा मतदाताओं के लिए ज्यादा अहम हो सकता है। खास तौर से वैसे युवा जो पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक हैं और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में चिंतित हैं। बता दें कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने अपने पिछले घोषणापत्र में उन राज्यों में वनों की सुरक्षा और संवर्धन की सुविधा के 'हिमालयी क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित मांग' को पूरा करने का वादा किया था। इसके लिए 'ग्रीन बोनस' का जिक्र घोषणा पत्र में था। लेकिन 2023-24 के बजट में भी ग्रीन बोनस का जिक्र नहीं किया गया था। बीजेपी ने अपने पिछले घोषणापत्र में गांवों के लिए विद्युतीकरण, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण जल संरक्षण और भूजल की कमी को 2024 तक पूरा करने का वादा किया था। साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के तहत 102 प्रदूषित शहरों पर ध्यान केंद्रित करने का भी वादा किया था। कांग्रेस ने भी अपने घोषणापत्र में मिट्टी की बिगड़ती गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही थी। कांग्रेस ने जल निकाय बहाली मिशन और बंजर भूमि पुनर्जनन मिशन को बढ़ावा देने की जरूरत को अपने घोषणापत्र में शामिल किया था।

भारत के लिए जल संकट बड़ी चुनौती

भारत बढ़ती आबादी के साथ तेजी से जल संकट की ओर बढ़ रहा है। यही वजह है भूजल संसाधनों और नदियों को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कई बड़ी नदियां मौजूदा समय में अबतक के सबसे खराब हालात से गुजर रही हैं। देश भर के प्रमुख शहरों और नदियों में प्रदूषण की बड़ी चिंताएं बनी हुई हैं। पानी की कमी जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है।

जलवायु परिवर्तन से हो रही दुश्वारियों का समाधान ढूंढने की जरूरत

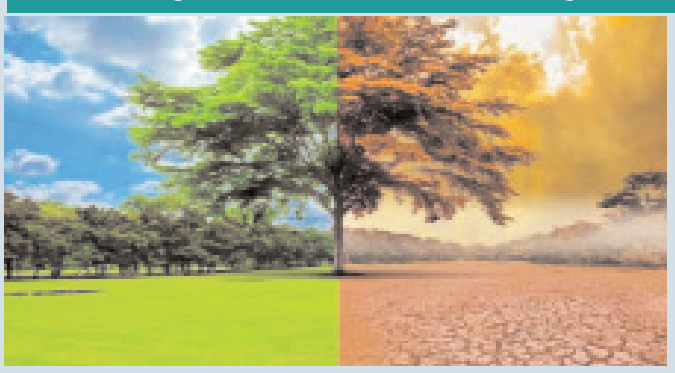

जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका समाधान खोजने के लिए दृष्टिकोण की जरूत है। भारत में सांसदों ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है और नीतियों में बदलाव के लिए जोर देने की कार्रवाई की मांग की है वो इस मुद्दे की गंभीरता को पेश करता है। वहीं जलवायु परिवर्तन पर जन जागरूकता के मामले में भारत ने अमेरिका और रूस जैसे विकसित देशों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। येल प्रोग्राम ऑफ क्लाइमेट चेंज कम्युनिकेशन सर्वे में पाया गया कि 84 प्रतिशत भारतीयों का मानना है कि इंसानी गतिविधियों की वजह से जलवायु परिवर्तन उपजा है। इस आंकड़े से पता चलता है कि अधिकांश भारतीय जलवायु परिवर्तन और इस मुद्दे की गंभीरता से रूबरू हैं, जो आम जनता के लिए चुनावों में वोट डालने के लिए अहम कारक हो सकता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने कहा है कि दुनिया भर में बढ़ती गर्मी व ताप लहरों की स्थिति से निपटने के उपाय प्रकृति में ही मौजूद हैं, और भविष्य में उच्च तापमान से होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए शहरी प्रशासन को प्राकृतिक समाधानों में निवेश शुरू कर देना चाहिए। अगस्त के महीने में दुनिया भर में तापमान बढ़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर चीन तक, अनेक देशों में इस समय झुलसा देने वाली तापलहर चल रही है। रोम के कोलोसियम जैसी जगहों पर पारा रिकॉर्ड 40 डिग्री सैल्सियस तक पहुँच गया। जिससे पर्यटक गर्मी में तप गए। मराकेश में तापमान 46.8 डिग्री सैल्सियस के चौंकाने वाले स्तर तक पहुँच गया। बीजिंग ने लगातार 28वें दिन 35 डिग्री सैल्सियस से ऊपर तापमान दर्ज कर एक चिन्ताजनक कीर्तिमान स्थापित किया। और फीनिक्स में, अमेरिका के अधिकांश दक्षिणी हिस्से में गर्मी का गुबार जमने के कारण लगभग 50 साल पुराना तापमान का रिकॉर्ड टूट गया।

गर्मी की तपन से बचने प्रकृति आधारित समाधान जरूरी

जैसे-जैसे दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ रहा है, रिकॉर्ड-तोड़ ताप लहरें और आम होने का अनुमान है। जिससे शहरों में व्यवधान होने की आशंका है, जो अपने पीछे मौतों के निशान छोड़ जाती है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि खासतौर पर तापमान वृद्धि के प्रति सम्वेदनशील शहरों में पेड़ लगाकर, जल निकायों को बहाल करके व अन्य प्राकृतिक समाधानों के जरिए, ताप लहरों को कुछ सबसे बुरे प्रभावों को रोका जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के उद्योग और अर्थव्यवस्था प्रभाग के उप निदेशक स्टीवन स्टोन ने कहा है कि प्राकृतिक दुनिया में तापमान कम करने के कई टिकाऊ व किफायती तरीके मौजूद हैं। कई नगर पालिकाओं को इसका ऐहसास होना शुरू हो गया है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली तीव्र गर्मी से निपटने दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जलवायु विशेषज्ञ लम्बे समय से बढ़ते तापमान और मानव स्वास्थ्य के लिए बढ़ते खतरों की चेतावनी दे रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर 2022 के अन्तर सरकारी पैनल की रिपोर्ट में अनियंत्रित तापमान वृद्धि का गम्भीर परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है जिसमें बढ़ती तापलहरें गर्मी का लम्बा मौसम और ठंड का सिकुड़ता मौसम आम होते जा रहे हैं।

शहर जहाँ 55 प्रतिशत मानवता रहती है। विशेष रूप से गर्मी से प्रभावित हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहर आम तौर पर 5°C से 9°C अधिक गर्म होते हैं क्योंकि कांक्रीट की इमारतें और फुटपाथ सूरज की रोशनी को सोखकर विकिरणित करते हैं। लोगों, कारों और मशीनरी की सघनता से भी तापमान में वृद्धि होती है।

अगर 2050 तक मानवता गम्भीरता से जलवायु परिवर्तनकारी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं घटाती तो लगभग 1,000 शहरों में गर्मियों में तापमान औसतन 35°C तक पहुँचेगा, जो वर्तमान संख्या से लगभग तीन गुना अधिक है। इस उच्च तापमान के सम्पर्क में आने वाली शहरी आबादी 800 प्रतिशत तक बढ़ सकती है, जो सदी के मध्य तक एक अरब 60 करोड़ तक पहुँचने की अपेक्षा है। तीव्र गर्मी अक्सर घातक होती है। 'नेचर मेडिसिन जर्नल' के एक नए अध्ययन में पाया गया कि केवल योरोप में ही साल 2022 के दौरान गर्मी के मौसम में ताप सम्बन्धित बीमारियों से 61 हजार से अधिक लोगों की मौतें हुईं, जिनमें से अनेक मौतें शहरों में हुई थीं।

UN-Habitat की प्रमुख वैश्विक ताप अधिकारी एलेनी माइरिविली ने कहा उचित जागरूकता, संसाधन उपयोग और जवाबी कार्रवाई से गर्मी से होने वाली बीमारियों व मौतों को रोका जा सकता है। जिनमें से अनेक कार्रवाइयाँ शहरी स्तर पर लागू की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि शहरों में तीव्र गर्मी की शुरुआती चेतावनी जारी करके व शीतलन केन्द्र खोलकर गर्मी से जुड़े खतरों को कम किया जा सकता है। साथ ही हरित स्थानों और प्रकृति में 'मौलिक वृद्धि' की जा सकती है।

> **धरती पर बढ़ती तपन को लेकर विश्व के अनेक देश आज हलाकान है। फिनिक्स और अमेरिका के अधिकांश दक्षिणी हिस्सों में उठते गर्मी के गुबार ने लगभग 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में आज सभी देश वृक्षारोपण से धरती पर बढ़ती तपन रोकने का बेहतर उपाय मान रहे है।**

UNEP के आँकड़ों से पता चलता है कि केवल शहर की सड़कों पर पेड़ लगाने से 7 करोड़ 70 लाख लोगों को गर्म दिनों में 1 डिग्री सैल्सियस की राहत मिल सकती है। सामान्य धूप वाले एक दिन में एकमात्र पेड़ भी कई सौ लीटर पानी सोख सकता है। जिसका प्रभाव 24 घंटे चलने वाले दो घरेलू एयर कंडीशनरों के बराबर होगा।

शहरी वन और बड़े पार्क भी गर्म हवा को जमीनी स्तर से ऊपर उठाकर और ठंडी हवा फैलाकर अपनी सीमा से लगभग 1 किमी दूर तक शीतलन लाभ प्रदान करते हैं। हरे स्थानों को परस्पर जोड़ने से पवन गलियारे बनते हैं जो स्थानीय तापमान को घटाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में झीलों, नहरों, तालाबों और आर्द्रभूमि जैसे जल निकायों को संरक्षित करने से महत्वपूर्ण ठंडक प्राप्त हो सकती है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में बढ़ते तापमान और आस-पास के जंगलों में लगी आग से बुरी तरह प्रभावित शहर के अधिकारी शहर के केन्द्र तक जाने वाले 24 किमी के हरे-भरे शीतलन गलियारे की सिंचाई के लिए रोमन-युग के जलसेतु का उपयोग कर रहे हैं।

यह प्राकृतिक समाधान विशेष रूप से अहम इसलिए भी हैं, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन में योगदान किए बिना तापमान को कम करने में मदद देते हैं। यह एयर कंडीशनिंग के बिल्कुल विपरीत है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक शक्तिशाली स्रोत है। शहरों में प्रकृति, प्राकृतिक आवासों का आपसी सम्पर्क व सहनसक्षमता बढ़ाने एवं जैव विविधता का समर्थन करने में मदद करती है। जो कि वर्ष 2022 में अपनाए गए वैश्विक जैव विविधता ढाँचे के अनुरूप है।

औषधीय पौधों को बढ़ावा देने से होगा पर्यावरण संरक्षण

श्रीराम माहेश्वरी
वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार, भोपाल

भारतीय संस्कृति और वेदों में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का हमें उल्लेख मिलता है। हमारे यहां आदिकाल से ही पेड़ों की पूजा करने का रिवाज रहा है ।भारत में औषधीय पौधों का रोपण और संरक्षण किया जाता रहा है ।वनस्पति शास्त्र का महत्व रहा, इसीलिए आयुर्वेद का प्रचलन भी निरंतर बढ़ा है ।पिछली महामारी के संकट के समय में आयुर्वेदिक औषधियों के सेवन से नागरिकों को अच्छा लाभ हुआ।मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आयुर्वेदिक औषधियां रामबाण साबित हुई हैं।प्रकृति में औषधीय पौधों का महत्व हमें समझना होगा तभी हम आयुर्वेद को बढ़ावा देने में समर्थ हो सकेंगे।सही मायने में इन पौधों और वनस्पतियों को बढ़ावा देने से ही पर्यावरण का संरक्षण होगा।

भारत में पिछले चार दशकों में उद्योगों को खूब बढ़ावा दिया गया। उद्योग धंधे भी बढ़े, परंतु औद्योगिक क्रांति के इस विकास के साथ-साथ प्रदूषण भी लगातार बढ़ता रहा। उद्योगों से निकलने वाला विषैला तरल पदार्थ और अपशिष्ट नदियों और जलाशयों में मिलने लगा। इसके परिणाम स्वरूप हमारे पेयजल स्रोत दूषित होते गए। भूमि में काफी नीचे तक इस हानिकारक पदार्थों ने नुकसान पहुंचाया। इससे कुएं, बावड़ी और हैंडपंप जैसे जल स्रोतों से हमें प्रदूषित जल मिलने लगा और दूषित जल के सेवन से लाखों लोगों का जीवन संकट में पड़ा। कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा। भूमि की उर्वरा शक्ति रासायनिक खाद के उपयोग से नष्ट होती चली गई। फसल कटाई के बाद किसान हर साल खेतों में नरवाई जलाते हैं। इससे भूमि के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और पक्षियों का भी भोजन नष्ट हो जाता है। इस तरह की समस्याओं का हमें समाधान खोजने की आवश्यकता है।

विश्व पर्यावरण दिवस हम हर साल पांच जून को मनाते हैं। इस दिन दुनिया के तमाम देशों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है। करीब एक सप्ताह तक तो लोगों में उत्साह बना रहता है और फिर स्थिति पूर्ववत हो जाती है। यदि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को हम अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लें, तो आने वाला समय हरित क्रांति का होगा। आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलता रहेगा।

वेदों और शास्त्रों में बताए गए सिद्धांतों पर चलकर हम अपने परिवेश को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। महानगर शहरों का अधिग्रहण कर रहे हैं और शहर और कस्बे गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रामीण परिवेश पर शहरी संस्कृति हावी होती जा रही है। इसका दुष्प्रभाव हमारे जनजीवन पर पड़ रहा है। बहुमंजिला इमारतें, सड़कें, पुलों का निर्माण, उद्योगों का विस्तार होने से कृषि भूमि लगातार कम होती जा रही है। पड़त और चरनोई की भूमि नष्ट होने से पशुओं को चारा नहीं मिल पा रहा है। इससे पशुओं की संख्या भी कम हो रही है। वनों के घटने और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट होने से वन्य प्राणियों के जीवन पर भी संकट खड़ा हो रहा है। वे जंगल छोड़कर अब गांव और शहरों में आने लगे हैं। जंगलों में मानवीय गतिविधियां बढ़ने से और शोर बढ़ने से पशु पक्षियों को रहन-सहन और प्रजनन की समस्या बढ़ी है। जिससे उनके जीवन पर भी संकट बढ़ रहा है। भारत में पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव का असर शहरों के साथ-साथ गांव में भी देखने को मिल रहा है। खेतों में रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बिजली के लिए हमें सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाना होगा।

सार्वजनिक परिवहन के लिए हमें बड़ी डीजल बसों की बजाय छोटे बैटरी के वाहन उपयोग में लाने होंगे। इससे प्रदूषण नहीं होगा। डीजल कारों की बजाय पेट्रोल कारों के चलन को बढ़ाना होगा। इससे कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण हो सकेगा। एसी और फ्रिज के बढ़ते प्रचलन को भी हमें हतोत्साहित करने की आवश्यकता है।

शहरों में कचरे के निस्तारण की समस्या विकराल रूप ले रही है। सड़कों और रेल पटरी के किनारे, गलियों और मोहल्लों में कचरे के ढेर नजर आ जाते हैं। नागरिकों को स्वच्छता की ओर ध्यान देना होगा। उन्हें नगर निगम और नगर पालिका के बजाय स्वयं की भी जिम्मेदारी समझनी होगी। स्वच्छता अभियान का हर नागरिक को हिस्सा बनना होगा, तभी हम कचरे का समाधान कर पाएंगे। किसी देश की जैव विविधता जितनी समृद्ध होगी, वह देश भी उतना ही अधिक खुशहाल होगा। इसलिए हमें पेड़ पौधों और वनस्पतियों का संरक्षण करना होगा। हर नागरिक अपने घर के आस-पास कम से कम दो पेड़ लगाए। उनका संरक्षण करें। स्वच्छता का ध्यान रखें। ध्वनि, वायु ,भूमि और जल प्रदूषण को रोकने की दिशा में वे अपना योगदान दें तभी हम सही मायने में पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे।

बिजनेस को पर्यावरण के अनुकूल बनाएं : प्रधानमंत्री

दिल्ली में आयोजित बी 20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में 23 अगस्त से उत्सव का माहौल है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान के कई उपकरण देश में बने। पीएम ने कहा कि बी 20 में भी अफ्रीका के डेवलेमेंट को एक फोकस एरिया में रखा गया है। यह फोरम जितना बड़ा होगा, उतना ही फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी आपदा आती है, बड़ा संकट आता है तो वह हमें कुछ ना कुछ सबक देकर जाता है। दो-तीन साल पहले हम दुनिया की सबसे बड़ी महामारी से गुजरे हैं जो दुनिया को एक सबक देकर गई।

भारत ने बिजनेस के लिए ग्रीन क्रेडिड का फ्रेमवर्क तैयार किया

कोरोनाकाल में दिखी भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड 19 संकट ने दुनिया के हर देश को हर समाज को हर बिजनेस हाउस को एक सबक दिया है। सबक ये है कि हमें जिस पर सबसे अधिक इंवेस्ट करना है, वो है आपसी विश्वास। कोरोना ने इस आपसी विश्वास को तहस नहस कर दिया है। अविश्वास के माहौल में जो देश आपके सामने पूरे विश्वास का झंडा लेकर खड़ा है वो भारत है। भारत ने दुनिया को जो चीज दी है वो है विश्वास। भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाईयां उपलब्ध कराई। जब दुनिया को कोविड वैक्सीन की जरूरत थी, तो भारत ने वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाकर करोड़ों-करोड़ों लोगों की जान बचाई। भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज उसके एक्शन में दिखती है। भारत के रिस्पांस में दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन तथा पृथ्वी को बचाने जैसे विषयों पर भी विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने लोगों की लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाने का आव्हान करते हुए स्वास्थ्य के मुद्दे पर केवल डायनिंग टेबल पर होने वाली चिंता को दैनिक जीवन में भी बरकरार रखने की बात कही।

प्रधानमंत्री ने किया सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन का किया जिक्र

ग्रीन एनर्जी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में हम ग्रीन एनर्जी पर बहुत अधिक बल दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो सफलता भारत को मिली है इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी दोहराएं। भारत की कोशिश इसमें भी दुनिया को साथ लेकर चलने की है। यह कोशिश इंटरनेशनल सोलर एलायंस के तौर पर भी दिखाई देती है। कोरोना के बाद की दुनिया में हम देखते हैं कि अपनी हेल्थ को लेकर सभी बहुत जागरूक हो गए हैं। स्वास्थ जागरूकता डायनिंग टेबल पर तो तुरंत दिखती है, जब हम कुछ खरीदते हैं, खाते हैं जो काम करते हैं, हर चीज में ये जरूर देखते हैं कि इसका हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर कोई ये सोचता है कि इससे भविष्य में कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। यानि आज का नहीं बल्कि भविष्य का भी सोचते हैं। यही सोच बिजनेस और सोसायटी की प्लैनेट को लेकर भी होनी चाहिए।

सभी लोग करें पृथ्वी की चिंता

पीएम मोदी ने कहा कि जितनी चिंता मुझे मेरे हेल्थ के लिए हो, उतनी ही चिंता प्लेनेट की करना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। हर फैसले से पहले इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए कि इसका हमारी धरती पर क्या असर होगा। लाइफस्टाइल के पीछे यही भावना है। लाइफस्टाइल के हर डिसीजन का असर बिजनेस वर्ल्ड पर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। जब लाइफस्टाइल और बिजनेस दोनों प्रो प्लेनेट होंगे तो समस्याएं वैसी ही कम हो जाएंगी। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि कैसे हम अपने बिजनेस को पर्यावरण के अनुकूल के हिसाब से बनाएं। भारत ने बिजनेस के लिए ग्रीन क्रेडिड का फ्रेमवर्क तैयार किया है। हम इतने दिनों से कार्बन क्रेडिट में उलझे हुए हैं। ग्रीन क्रेडिट प्लेनेट पॉजिटिव एक्शन पर जोर देता है। उन्होंने कहा कि मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वो इससे जुड़ें और इसे ग्लोबल मूवमेंट बनाएं।

तपती धरती संपादक मण्डल
सलाहकार संपादक गौरीशंकर मुकाती
संपादक प्रहलाद शर्मा
प्रबंध संपादक श्रीराम माहेश्वरी, भोपाल
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि संदीप राय चौधरी, सिंगापुर
राष्ट्रीय प्रतिनिधि विक्रांत तिवारी, मुम्बई